जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोन:- 2418945 फैक्स:- 0294-2410146 वर्ष: 32 संख्या: 71 प्रभात उदयपुर, रविवार 12 जनवरी, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

तथाकथित सी.ए.जी. रिपोर्ट, दिल्ली के चुनाव में निर्णायक साबित हो रही है

भाजपा के अनुसार, केजरीवाल सरकार की एक्साइज़ पॉलिसी के कारण दिल्ली की सरकार को 2026 करोड़ रूपए का नुकसान उठाना पड़ा है

- आप के सांसद संजय सिंह ने इस तथाकथित सी.ए.जी. रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाये और कहा, यह रिपोर्ट भाजपा के कार्यालय में लिखी गई है।
- इसी संदर्भ में संजय सिंह ने कहा कि एक तरफ तो भाजपा कहती है कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट ''टेबल'' नहीं हुई है, दूसरी ओर कहते हैं कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट ''रिलीज़'' हो गई है। आखिर भाजपा कहना क्या चाहती है।
- भाजपा ने सी.ए.जी. की तथाकथित रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को 890 करोड़ रूपए का नुकसान तो केवल इसलिये हुआ कि जो शराब की दुकान के लाइसैंस सरैण्डर हो गये थे, उन दुकानों के लाइसैंस री टेन्डर नहीं किये गये। इसके अलावा 941 करोड़ रूपए का अन्य नुकसान इसलिए हुआ कि ज़ोनल लाइसैंस धारकों को गैर कानूनी स्वीकृति दी गई।
- भाजपा के अनुसार, उपराज्यपाल, कैबिनेट तथा विधानसभा से वे स्वीकृतियां प्राप्त नहीं की गईं जो ये रियायतें देने से पहले कानूनन लेना अनिवार्य था।
- भाजपा का यह भी आरोप है कि मंत्रियों के समूह के संबंध में विशेषज्ञों के पैनल की रिपोर्ट व सिफारिशों का भी अनुसरण नहीं किया गया।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 जनवरी। भाजपा ने आज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (सी.ए.जी.) की रिपोर्ट के कथित निष्कर्षों को लेकर ''आप'' पर हमले तेज कर दिये। सी.ए.जी. की यह रिपोर्ट शहर की विवादास्पद आबकारी नीति से संबंधित है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की इस कोशिश से उत्तेजित आप नेता संजय सिंह ने पलटवार करते हुये, इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किये तथा पूछा कि क्या ये कथित निष्कर्ष भाजपा कार्यालय में तैयार किये गये हैं।

इस रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व के अन्तर्गत, कथित रूप से बड़ी खामियों एवं उल्लंघनों का खाका प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद, 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एक नया उपद्रव खड़ा हो गया है।

चौंकाने वाली बात यह है कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट्स विधानसभा चुनावों के प्रचार-अभियान के दौरान जारी या लीक की जा रही हैं। इससे ये संदेह पैदा हो रहे हैं कि क्या सी.ए.जी. भाजपा का चुनावी पार्टनर हो गया है, जो भाजपा के मुख्य प्रतिद्वंदी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार करके, सत्तारूढ़ दल (आप) को हराना चाहता है।

सी.ए.जी. रिपोर्ट अधिकृत रूप से जारी नहीं की गई है। आरोप लगाया गया है कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के कारण राज्य को 2026 करोड़ रूपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस राशि में 890 करोड़ रूपए का वह नुकसान भी शामिल है, जो ''सरैंडर'' कर दिये गये फुटकर शराब लाइसैंसों की पुन: निविदा के असफल हो जाने के कारण हुआ, इसके अलावा 941 करोड़ रूपए का अतिरिक्त नुकसान कथित रूप से ज़ोनल लाइसैंसों को दी गई छूटों के कारण हुआ है।

लेफ्टिनेन्ट गवर्नर (एल.जी.), मंत्रिमंडल तथा विधानसभा के मुख्य अनुमोदन कथित रूप से बाईपास कर दिये गये। रिपोर्ट आगे कहती है कि मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाले ग्रुप

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिल्डर पर 2.31 लाख रूपये का हर्जाना

जयपुर, 11 जनवरी। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय ने लॉटरी में आवंटित किए गए फ्लैट का कब्जा तय समय पर नहीं देने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार देते हुए मैसर्स यूनिक बिल्डर्स एंड डवलपर्स पर 2.31 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं जमा करवाई गई राशि भी 9 फीसदी ब्याज सहित लौटाने के लिए कहा है। आयोग ने होम लोन देने वाली फाइनेंस कंपनी को निर्देश दिया है कि वह विपक्षी बिल्डर से लोन के तौर पर दी गई राशि की वसूली करे और परिवादी की सिबिल

- जिला उपभोक्ता आयोग ने यूनिक बिल्डर्स एंड डवलपर्स पर तय अवधि में फ्लैट का कब्जा नहीं देने पर यह हर्जाना लगाया।

को भी दुरुस्त करे। आयोग के अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर व सदस्य दुष्यंत कुमार शर्मा ने यह आदेश कृष्णा देवी के परिवाद पर दिए। परिवाद में कहा गया कि विपक्षी बिल्डर ने साल 2019 में जयपुर अजमेर एक्सप्रेस वे पर यूनिक अभिनंदन के नाम से आवासीय योजना लांच की। इसमें परिवादिया को मुख्यमंत्री जन आवासीय योजना के तहत ईडब्ल्यूएस केटेगरी में 374 वर्ग फीट का फ्लैट 8.51 लाख रुपए में लॉटरी के जरिए आवंटित किया गया। इसके लिए विपक्षी बिल्डर ने उसे फाइनेंस कंपनी से लोन भी दिलवा दिया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली विधानसभा चुनावों में तीनों पार्टियां महिला वोटर्स को लुभाने में लगी हैं

तीनों पार्टियां महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक वजीफे घोषित कर रही हैं

- आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतने पर सभी महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह 2100 रूपए ट्रांसफर करने का वादा किया है।
- भाजपा और कांग्रेस ने इससे भी आगे बढ़कर घोषणा की और महिलाओं को ढाई हजार रूपए प्रति माह देने का वादा किया। भाजपा की ''लखपति दीदी'' की तर्ज पर कांग्रेस ने अपनी योजना का नामकरण ''प्यारी दीदी'' किया है।
- इन घोषणाओं का नतीजा यह रहा कि 16 दिसम्बर से 6 जनवरी के बीच जिन 5.1 लाख वोटर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया, उनमें से 70 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- महिला मतदाताओं की इस पर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अधिकांश महिलाओं ने इसका स्वागत किया, वहीं कई अन्य ने इसके दूरगामी प्रभाव पर सवाल उठाए।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 जनवरी। पाँच फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले, तीनों प्रमुख पार्टियाँ, महिला मतदाताओं के बैंक खातों में सीधे धनराशि ट्रांसफर के लुभावने वादे करके, उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी (आप) ने हर महिला को 2100 रूपये प्रति माह देने का वादा किया है, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पेशकश बढ़ाकर 2500 रूपए प्रति माह कर दी है।

यह पेशकश दिल्ली की महिलाओं के लिये है, जो दिल्ली के मतदाताओं की 46.2 प्रतिशत हैं।

दिल्ली के चीफ इलैक्ट्रोरल ऑफिसर (सी.ई.ओ.) कार्यालय द्वारा 6 जनवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में कुल 1,55,24,858 रजिस्टर्ड मतदाता हैं, जिनमें 83,49,645 पुरुष तथा 71,73,952 महिलाएं हैं।

आप का फोकस कल्याण-केन्द्रित प्रचार तथा ''महिला सम्मान योजना'' के अंतर्गत, महिलाओं को 2100 रूपए प्रति माह देने पर है, जबकि कांग्रेस ने ''प्यारी दीदी योजना'' के अंतर्गत 2500 रूपए प्रति माह देने का वादा किया है। इन घोषणाओं ने मतदाता-रजिस्ट्रेशन पर ठोस असर किया है। 16 दिसम्बर से 6 जनवरी के बीच, दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास नये मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन 5.1 लाख आवेदन आये, जो सर्वथा अप्रत्याशित संख्या थी। इनमें से करीब 70 प्रतिशत (लगभग 3.4 लाख) आवेदन महिलाओं के थे।

इस मासिक वित्तीय सहायता के वादों पर दिल्ली की महिला मतदाताओं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोमवार को दिल्ली में राहुल पहली चुनावी रैली करेंगे

दिल्ली के ए.आई.सी.सी. प्रभारी काज़ी निजामुद्दीन ने कहा, राहुल सीलमपुर में रैली करेंगे

- दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे और 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे। कांग्रेस इस बार अपनी तरफ से भारी कोशिश कर रही है, चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के लिए।
- इसके लिए नवम्बर में ''दिल्ली न्याय यात्रा'' आयोजित की गई थी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा व भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ आयोजित यह यात्रा 7 दिसम्बर को समाप्त हुई थी। कांग्रेस को यकीन है कि इस यात्रा से जनता में उसकी पैठ बढ़ी है।
- 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में क्रमशः 67 और 62 सीटें लेकर आप विजयी हुई थी। भाजपा को 2015 में तीन व 2020 में 8 सीटें मिली थीं पर 15 साल सत्ता में रही कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका था।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 जनवरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 13 जनवरी को दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करेंगे। शनिवार को यहाँ एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में यह बताते हुये, एआईसीसी प्रभारी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि राहुल देश की जनता की आवाज के रुप में उभरे हैं।

पाँच फरवरी को होने वाले दिल्ली के चुनाव से लगभग तीन सप्ताह पूर्व, राहुल गांधी पूर्वोत्तर दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र से दिल्ली चुनाव के लिये अपना प्रचार-अभियान शुरु कर रहे हैं। इस सभा में जहाँ बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित होंगे, वहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी भागीदारी रहेगी।

कांग्रेस ने नवम्बर में एक महीने की ''दिल्ली न्याय यात्रा'' संचालित की थी, ताकि विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं से सम्पर्क हो सके तथा पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ सके। गांधी की ''भारत जोड़ो यात्रा'' और ''भारत जोड़ो न्याय यात्रा'' के अनुरुप आयोजित की गई यह यात्रा 7 दिसम्बर को समाप्त हुई थी।

ज्ञातव्य है कि 2015 और 2020 में हुये दिल्ली विधानसभा चुनावों में आप ने क्रमश: 67 और 62 सीटें जीती थीं। भाजपा 2015 में 3 तथा 2020 में 8 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस इन चुनावों में कोई सीट नहीं जीत पाई थी।

छात्र को फॉरेन मैडिकल ग्रेजुएट परीक्षा में शामिल करने के निर्देश

जयपुर, 11 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने विदेश से एमबीबीएस की डिग्री पास करने वाले छात्र को नीट की अंक तालिका के अभाव में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा में शामिल नहीं करने को गलत माना है। इसके साथ ही अदालत ने एनबीई के अध्यक्ष को कहा है कि वह याचिकाकर्ता छात्र को

- नीट की अंक तालिका के अभाव में याचिकाकर्ता को परीक्षा में शामिल नहीं किया गया, जबकि, अंक तालिका खोने की शिकायत दर्ज कराई हुई थी।

एफएमजी परीक्षा में शामिल करें। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश चिन्मय उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के नीट-2019 में शामिल होने के बाद उसे योग्य घोषित किया गया था। वहीं उसकी ईमानदारी इससे भी साबित है कि उसने स्कोर अंक तालिका लापता होने पर इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। वहीं एनटीए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रेल लाइन के जरिए कश्मीर के मतदाताओं की ''स्वीकृति'' मिलने की उम्मीद है भाजपा को

26 जनवरी से कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन शुरु करने की योजना अंतिम चरण में पहुँची

- रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने 111 किलोमीटर लम्बे कटरा-बनिहाल सैक्शन को ''सिक्यूरिटी क्लियरैंस'' दे दिया है।
- सैक्शन में 97 किलोमीटर भाग सुरंगों से और शेष दूरी चार बड़े पुलों के मार्फत तय की जाएगी। इसमें ''चिनाब ब्रिज'' भी है जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है।
- इस मार्ग के लिए अभी दो स्पेशल वंदे भारत चेयर कार डिज़ाइन की गई हैं, जिनमें एडवांस हीटिंग सिस्टम है।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 जनवरी। भारतीय रेलवे ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के कगार पर है, 26 जनवरी को कटरा से श्रीनगर तथा उससे आगे ट्रेन संचालन शुरु करने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामुला रेल लाइन (यू.एस.बी.आर.एल.) का निर्माण कार्य दो दशकों से चल रहा है और इस दौरान सामने आईं अनेक इंजीनियरिंग चुनौतियों के कारण मूल डीटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट (डी.पी.आर.) में कई तरह की तब्दीलियाँ हुई हैं।

कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (सी.आर.एस.) ने कटरा को बनिहाल से जोड़ने वाले बहुत समय से लंबित तथा अति महत्वपूर्ण एक सौ ग्यारह किलोमीटर लंबे सैक्शन को मंजूरी दे दी है। इस सैक्शन का 97 कि.मी. भाग सुरंगों से गुज़रता है तथा 7 कि.मी. की दूरी चार बड़े पुलों के ऊपर से तय करनी पड़ती है, जिसमें चेनाब ब्रिज भी शामिल है, जिसे विश्व का सबसे ऊँचा रेल ब्रिज माना जाता है।

कश्मीर घाटी में दो ट्रेनें पहले से चल रही हैं और दिल्ली के शकूर बस्ती यार्ड में विशेष रूप से डिज़ाइन की गई दो वंदे भारत चेयर कार बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। इन ट्रेनों में एडवांस्ड हीटिंग सिस्टम है, जो वॉटर टैंक तथा टॉयलैट के टैंक के पानी को जमने नहीं देता और वैक्युम सिस्टम के लिए गर्म हवा मुहैया करवाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शून्य से नीचे के तापमान में भी एयर-ब्रेक सिस्टम सुचारु रुप से काम करता रहे। इस समय संचालित हो रहीं अन्य ''वंदे भारत'' ट्रेनों की तरह ही, ये ट्रेन पूरी तरह एयर-कन्डीशन्ड होंगी तथा इनके दरवाजे ऑटोमैटिक होंगे। इनसे कटरा और श्रीनगर के बीच की दूरी करीब तीन घंटे में तय हो जाने की संभावना है।

कटरा-बनिहाल सैक्शन के पूरा हो जाने तथा इसे सी.आर.एस. अनुमोदन मिल जाने के साथ ही, यू.एस.बी.आर.एल. भारतीय रेलवे के मेनलाइन नैटवर्क से जुड़ गया है तथा आगामी कुछ महीनों में ही, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक ट्रेन चल जानी चाहिये। रेल विभाग इस समय छोटे-मोटे परिवर्तनों तथा सुधारों (मॉडिफिकेशन) पर काम कर रहा है, जैसे- जम्मू स्टेशन का विस्तार। कटरा से श्रीनगर को जोड़ने वाले छोटे से टुकड़े पर रेल संचालन शुरु करने के निर्णय के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, लंबी दूरी की ट्रेनों के लिये वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर-संस्करण की आवश्यकता होगी, जो अभी ट्रायल के दौर में हैं। दूसरा, केन्द्र सरकार और, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, क्षेत्र की राजनैतिक संवेदनशीलता के चलते, इस ट्रेन को ''कश्मीर प्रोजैक्ट'' के रूप में समर्पित करना चाहते हैं।

जाहिर है, केन्द्र सरकार ने, एक राजनैतिक पहल के रूप में, हाल ही में जम्मू को एक नया रेलवे डिवीजन बनाने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'तृतीय पक्ष का अधिकार सृजित नहीं करें'

जयपुर, 11 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक के मालपुरा में 72 साल पहले भूमि की किस्म बदलकर उसे तलाई घोषित करने के मामले में तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित करने पर रोक

- हाई कोर्ट ने मालपुरा में भूमि की किस्म बदलने के मामले में आदेश दिया।

लगा दी है। जस्टिस अवनीश झिंगन की एकलपीठ ने यह आदेश मोहम्मद हुसैन शाह की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की पैतृक भूमि मालपुरा में स्थित है। साल 1995 में सेटलमेंट अधिकारी ने इस जमीन की किस्म बदलकर तलाई की जमीन के तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में चढा दी। इस पर याचिकाकर्ता ने मालपुरा एसडीओ के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बाँग्लादेश की सरकार ने वहाँ के दंगों व हिंसा की लीपा-पोती करने का प्रयास किया

बाँग्लादेश की सरकार के अनुसार, ये दंगें साम्प्रदायिक नहीं थे, केवल एक राजनीतिक घटनाक्रम का हिस्सा थे

- इस सरकारी विवरण के अनुसार, शेख हसीना की अवामी लीग की सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश था और शेख हसीना के हटने के बाद, यह जन आक्रोश फूट कर निकला तथा शेख हसीना के समर्थकों को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ा। हिंदू अधिकतर, अवामी लीग व शेख हसीना के पक्के समर्थकों में थे, अतः उन पर आक्रोश बरसा।
- इस थ्योरी के अनुसार, ये दंगे व हिंसा, सही मायनों में साम्प्रदायिक घटनाएं नहीं थीं।
- पर, बाँग्लादेश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह विवरण यह नहीं समझा पाया कि अगर दंगे साम्प्रदायिक नहीं थे तो हिंदू मंदिरों व संस्थाओं को ही क्यों ''टारगैट'' बनाया विध्वंसक कार्यवाही के लिये।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 जनवरी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमले को एक राजनैतिक घटनाक्रम बताकर वास्तविकता को छुपाने की कोशिश कर रही है।

एक पुलिस रिपोर्ट कह रही है कि हिंदुओं पर हुए हमले असल में साम्प्रदायिक प्रकृति के नहीं थे। ऐसी कुछ ही घटनाओं को स्वीकार किया गया है और उन पर थोड़ी कार्यवाही भी हुई थी। लेकिन इनको भी हल्का ही रखा गया और दोषियों पर कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं हुई।

देश की पुलिस ने इस हिंसा पर रिपोर्ट पेश की है जिन्हें शेख हसीना के हटने के बाद के राजनैतिक प्रतिशोध की संज्ञा दी गई है। वे इन हिंसक घटनाओं को राजनैतिक प्रकृति का बता रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना के जाने के बाद लोगों ने अवामी लीग के समर्थकों पर हमला किया था और अधिकांश हिंदू अवामी लीग के समर्थक हैं इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। पर पुलिस ने यह नहीं बताया कि हिंदू मंदिरों पर हमले क्यों हुए। लोगों ने हिन्दुओं के मकानों व दुकानों को निशाना बनाया।

भारत ने बांग्लादेश सरकार को नाराजगी जताते हुए कई नोट भेजे और सभी लोगों को सुरक्षा देने की बात कही। चाहे वे किसी भी धर्म के हों। बांग्लादेश के जमात-ए इस्लामी हिंदुओं के अलावा ईसाइयों तथा बौद्धों को निशाना बना रही है।

आश्चर्य की बात है जब यह हिंसा चल रही थी तब इंडियन हाई कमीशन ने भी मदद नहीं की और हिंदुओं को भारत आने का वीसा नहीं दिया।

यद्यपि भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार नागरिकता संशोधन बिल लाई, उसके अनुसार बांग्लादेश और पाकिस्तान में सताए जा रहे हिंदू अगर भारत आते हैं तो उन्हें स्वत: ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। लेकिन दूतावास व उच्चायोग उम्मीद पर खरे नहीं उतरे, उन्होंने ने एक अल्पसंख्यक परिवार के एक ही सदस्य को वीसा दिया है। बांग्लादेश सरकार ने भी हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर कोई कार्यवाही नहीं की। आधे अधूरे मन से जो कदम उठाए गए उन्हें लेकर अल्पसंख्यकों ने भारी विरोध जताया।

इन पीड़ितों का मत है कि भारत सरकार के ढीले रुख ने सांप्रदायिक ताकतों को और प्रोत्साहन दिया। सेना की स्थिति तो और भी खराब है। जब छात्र नेताओं ने हिंदुओ पर हमले का विरोध किया तो सेना ने उन्हें धमकी दी। छात्रों के आंदोलन ''स्ट्डेन्ट्स अगेन्स्ट डिसक्रिमिनेशन'' को बंद करवा दिया गया।

सेना के अधिकारी बांग्लादेश और पाकिस्तान में निकट सम्बंधों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, इससे छात्रों व हिंदुओं में असंतोष बढ़ रहा है हिंदू बांग्लादेश में अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

युवा दिवस पर 13 हजार नियुक्ति पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री

जयपुर, 11 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवा दिवस के अवसर पर रविवार को जयपुर स्थित बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में युवाओं को सरकारी नौकरियों की सौगात देंगे। इस अवसर पर राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यक्रमों के

- युवा दिवस पर राज्यस्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन।

माध्यम से लगभग 13 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा प्रदेशवासियों को लगभग 31 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे।

मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत चिकित्सा विभाग, वित्त विभाग, गृह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)